REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2023

सामाजिक ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका का अध्ययन (गोपालगंज जिला–बिहार राज्य के सन्दर्भ में)

मुश्ताक अहमद[1] , डॉ. आर.के. शर्मा[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राचार्य, इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश –

ग्रामीण विद्युतीकरण न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि भारत के द्वारा की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करने में मदद करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की लागत काफी अधिक है। ग्रामीण विद्युतीकरण आमतौर पर अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण नीति, वित्त और संस्थागत सेटअप के मामले में शहरी विद्युतीकरण की तुलना में अधिक चुनौतियाँ पेश करता है। कुछ सामान्य विशेषताएँ जो शहरी विद्युतीकरण की तुलना में ग्रामीण विद्युतीकरण को अधिक कठिन बनाती हैं, वे हैं प्रति किलोमीटर लाइन कनेक्शन की कम संख्या, खपत का निम्न स्तर, औद्योगिक भार की कमी, विषम परिदृश्य और निजी निवेशकों के लिए प्रेरणा की कमी। इन चुनौतियों के बावजूद, कुछ विकासशील देश अपनी ग्रामीण आबादी को बिजली उपलब्ध कराने में अधिक सफल रहे हैं।

मुख्य शब्द – सामाजिक, ग्रामीण विकास, विद्युतीकरण एवं गोपालगंज।

प्रस्तावना –

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक व वृत्तिक विकास में ईंधन के स्रोतों की उपलब्धता, ऊर्जा आपूर्ति एवं विद्युतीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किंतु ग्रामीण समाज के आर्थिक स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर में सुधार के लिए विद्युत सुविधा की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति एवं वितरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किंतु बिहार राज्य का गोपालगंज जिला उपर्युक्त समस्याओं से अछूता नहीं है। यद्यपि सामाजिक ग्रामीण विकास के सूचक के रूप में मानव समाज के विकास का सूचकांक का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मानव विकास सूचकांक वास्तव में प्रति व्यक्ति आय, दीर्घ आयु तथा साक्षरता पर आधारित है, जिससे आय के साथ–साथ मानवीय जीवन की गुणवत्ता भी प्रदर्शित होती है। ज्ञातव्य है कि सामाजिक ग्रामीण विकास की अवस्था की पहचान के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा तथा साक्षरता को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को एक साथ मानव विकास सूचकांक में इस प्रकार समायोजित किया कि इससे वास्तविक सामाजिक ग्रामीण विकास का ज्ञान हो सके। सामाजिक ग्रामीण विकास के अन्तर्गत अन्य तथ्यों के अतिरिक्त शिक्षा एवं साक्षरता स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, विद्युत वितरण, संवर्धन एवं भौतिक संवर्धन के अवसरों को बढ़ावा देती है जिससे समुचित ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्रत्येक घर तक सस्ती बिजली की पहुँच सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। हालाँकि, पिछले डेढ़ दशकों में विकास के एजेंडे में ग्रामीण विद्युतीकरण पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। 2005 में, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित अन्य सभी चल रही योजनाओं को शामिल किया गया। यह योजना विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के कार्यान्वयन के माध्यम से गाँवों के विद्युतीकरण पर केंद्रित है। आरजीजीवीवाई को बाद में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) (हाल ही में सौभाग्य योजना का नाम दिया गया) में शामिल किया गया था, जो अतिरिक्त रूप से फीडर पृथक्करण, उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार और घाटे को कम करने के लिए मीटरिंग पर केंद्रित है।[1]

ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता केवल उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों के आधार पर नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि पीक आवर्स के दौरान विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के प्रावधान के आधार पर भी मापी जानी चाहिए। ये दोनों अभी भी भारत के अधिकांश ग्रामीण परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली लगातार समस्याएँ हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अनुशंसित ऊर्जा प्लस दृष्टिकोण के अनुसार, केवल प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली की आपूर्ति ग्रामीण आजीविका विकास के लिए एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। यह ढांचा आय के लिए बिजली के उत्पादक उपयोग के साथ संयोजन में ऊर्जा पहुँच पर जोर देता है। हालाँकि, आय–सृजन गतिविधियों के लिए सीधे बिजली का उपयोग करने के लिए, बाजार की उपलब्धता, वित्तीय और तकनीकी सहायता के अलावा, उपकरणों का स्वामित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकरण का स्वामित्व, बदले में, घर की आर्थिक स्थिति और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। इससे समस्या और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा, घर पर और आय–सृजन गतिविधियों के लिए ऊर्जा तक पहुँच की कमी, उच्च स्तर की गरीबी, कम उत्पादकता, भारी काम का बोझ, महिला सुरक्षा के मुद्दे, छूटे हुए शैक्षिक अवसर और स्वास्थ्य जोखिमों के उच्च जोखिम से जुड़ी है।

विश्लेषण –

अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य का गोपालगंज जिले की सामाजिक ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गई है। जिले के ग्रामीण समाज में कृषि का महत्व, अधिकांश नागरिकों की आय एवं रोजगार की निर्भरता के ही कारण नहीं है। अपितु यहाँ की जीवन शैली का अभिन्न अंग है। विगत पांच वर्षों से कृषि सम्बन्धित ग्रामीण, सामाजिक संस्थाओं तथा नीतियों में बदलाव की बात बार–बार उठाई गई और उसे दोहराती रही है। जिले में सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 1/2 आधा हिस्सा से कुछ कम ही ग्रामीण समाज में कृषि से प्राप्त होता है। विगत कुछ वर्षों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दर चिन्ता का विषय हमेशा से ही बनी रही है। ग्रामीण समाज के विकास के लिए विद्युत आपूर्ति एवं सघन विद्युतीकरण के द्वारा सुधार की विशेष आवश्यकता है। झारखण्ड विभाजन से जिले में उत्पन्न बिजली संकट को दूर करने तथा सामाजिक ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे सकारात्मक प्रभाव, इस पर निर्भर जनसंख्या की आय एवं रोजगार की स्थिति पर पड़ सके।[2]

अध्ययनगत जिला गोपालगंज के एकीकृत ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की गतिविधि तीव्र नहीं है। जिले के सामाजिक–आर्थिक ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण का भरपूर योगदान नहीं मिल सका है। तमाम सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न प्रकार से शासन द्वारा बनाई गई नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन के बाद भी लगभग सैकड़ों ग्राम विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित पाये गये हैं। जिले के कुल 1566 ग्रामों में 1405 ग्रामों को विद्युतीकरण की योजना का लाभ मिल सका है। शेष ग्राम विद्युतीकरण की योजना के लाभ से वंचित पाये गये हैं। यद्यपि जिले में विद्युतीकृत ग्रामों में बिजली की समस्या आये दिन बनी रहती है। अनियंत्रित बिजली आपूर्ति एवं अघोषित बिजली कटौती की समस्या का निराकरण आज भी नहीं हो सका है। जिले में बढ़ती विद्युत की माँग की तुलना में विद्युत आपूर्ति नगण्य स्थिति में परिलक्षित होती है। आये दिन विद्युत चोरी के मामले देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती, अनियंत्रित बिजली आपूर्ति की समस्या और अधिक गंभीर पायी गयी है। विद्युतीकरण की कमी एवं विद्युत कटौती का प्रतिकूल प्रभाव एकीकृत ग्रामीण विकास के साथ ही समस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषकों के कृषि उत्पादन में कमी, खाद्यान्न आपूर्ति तथा खाद्यान्न की समस्या के

साथ पोषण स्तर में कमी तथा सकल पोषण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर है। अतः सारणी क्रमांक 1 की सहायता से जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति निम्नानुसार प्रदर्शित है –

सारणी क्रमांक 1
जिला गोपालगंज ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति, वर्ष 2021–22

क्र.	तहसील	तहसीलवार कुल ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्राम	जिले के कुल ग्रामों की तुलना में बिजली कृत ग्रामों का प्रतिशत
1	बैकुण्ठपुर	121	108	89.25
2	बरौली	81	70	86.41
3	भोर	172	158	91.86
4	विजयपुर	143	122	85.31
5	गोपालगंज	73	73	100.00
6	हथुआ	108	108	100.00
7	कटैया	117	117	100.00
8	कुचाईकोट	222	198	89.18
9	मांझा	111	102	91.89
10	पंचदेवारी	99	82	82.82
11	फुलवरिया	106	92	86.79
12	सिंघवलिया	67	46	68.65
13	थावे	53	53	100.00
14	उचका गांव	83	76	91.56
	कुल योग	1566	1405	89.71

स्रोत – ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार बिहार, आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2021–22

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 1 में गोपालगंज जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति तहसीलवार (वर्ष 2021–22) आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। उक्त सारणी में तहसीलवार कुल ग्रामों में से विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या तथा कुल ग्रामों की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या तथा कुल ग्रामों की तुलना विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत स्पष्ट किया गया है। जिले में कुल 1566 ग्रामों में से 1405 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्व हो चुका है। जिले में कुल चार तहसीलों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। 100 प्रतिशत विद्युतीकत ग्राम वाली प्रमुख तहसीलें, गोपालगंज, हथुआ, कटैया एवं थावे तहसील शामिल हैं। गोपालगंज तहसील में कुल 73 ग्राम, हथुआ 108, कटैया 117 तथा 53 ग्राम थावे तहसील में शत प्रतिशत विद्युतकृत हैं। जिले के तहसीलवार विद्युतीकरण के प्रतिशत में काफी अंतराल पाया गया है। इस अंतराल के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। जिले के पंच देवरी, फलवरिया, सिघवलिया, विजयपुर आदि तहसीलों में लगभग एक चौथाई ग्राम विद्युतीकृत की सुविधा से वंचित पाये गये हैं।

विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित ग्रामों के पीछे भौतिक कारण एवं मानवीय कारण उक्त दोनों उत्तरदायी हो सकते हैं। जिले की इन तहसीलों के ग्रामों के पीछे भौतिक कारण जैसे धरातलीय संरचना, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय कारणों में आर्थिक स्तर, सामाजिक संरचना, शैक्षणिक स्तर, आवागमन के साधन, राजनैतिक जागरूकता का अभाव तथा विद्युतीकरण सम्बन्धी शासन की योजनाओं और नीतियों की जानकारी का अभाव आदि प्रमुख कारण परिलक्षित होते हैं। यद्यपि जिले में विद्युत वितरण एवं विद्युत आपूर्ति की सुविधा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाकर हर घर बिजली पहुंचाने का प्रयास किया गया है। किंतु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रवार विद्युत वितरण से स्पष्ट होता है कि योजनाओं और सरकारी नीतियों का प्रभाव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत न्यूनतम पाया गया है। तहसीलवार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या एवं प्रतिशत से क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। सम्पूर्ण जिले की कुल 14 तहसीलों को यदि विद्युतीकरण की सुविधा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाय तो प्रतिशत के आधार मानकर कुल तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम

श्रेणी में ऐसी तहसीलें जहाँ के शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण की शासन द्वारा चलाई गई योजना का भरपूर लाभ मिला है। ऐसे ग्रामों में हर घर बिजली की सुविधा मिल चुकी है। शत प्रतिशत विद्युतीकृत ग्राम वाली तहसीलों को उच्च विद्युत आपूर्ति की श्रेणी में शामिल किया गया है। द्वितीय श्रेणी में जिले की ऐसी तहसीलों को शामिल किया जा सकता है। जहाँ 10 से 15 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण के लाभ से वंचित है। ऐसे ग्रामों को मध्यम श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत जिले की प्रमुख तहसीलें जैसे बैकुण्ठपुर, वसैली, उचका ग्राम, माझा, भोरे, कुचाई कोट आदि को शामिल किया गया है तथा तृतीय श्रेणी अथवा न्यूनतम विद्युतीकृत प्रतिशत वाली तहसीलों के ग्राम जहाँ 10 से 15 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। ऐसे ग्रामों में बिजली नहीं पहुंच सकी है। जिले की प्रमुख तहसीलें सिंधवलिया पंचदेवरी आदि हैं। इन ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना का लाभ न पहुंचने के पीछे भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।[3]

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः अध्ययनगत जिला गोपालगंज के एकीकृत ग्रामीण विकास में क्षेत्रवार, तहसीलवार विद्युतीकृत ग्रामों के प्रतिशत से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिले में विद्युत वितरण, विद्युत आपूर्ति में क्षेत्रीय अंतराल परिलक्षित पाया जाता है। यदि जिले में शत प्रतिशत हर घर बिजली सुविधा सुलभ हो सके तो सम्पूर्ण जिले का एकीकृत ग्रामीण विकास के साथ सम्पूर्ण जिले के समग्र विकास में तीव्रता सुनिश्चित हो सकेगी।

संदर्भ ग्रन्थ –

[1] अहसन कमर एण्ड अहमद इमतयाज (2016) – बिहार एक परिचय, नेशनल पब्लिकेशन, खजाँची रोड, पटना, ग्यारहवाँ संस्करण, पृष्ठ 147

[2] सलोना, श्याम (2020) – बिहार समग्र अध्ययन, के.बी.सी., नैनो पब्लिकेशन, प्राइवेट लिमिटेड, राजेन्द्र नगर, वामार मार्ग, नई दिल्ली, पंचम संशोधित संस्करण, पृष्ठ 217

[3] District Census Hand Book, Gopalganj, Bihar, Year 2011-2012